

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 24 जून, 2009

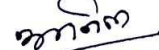
विषय:- विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की फी-होल्ड सम्पत्तियों पर लेबी (अनिर्माण शुल्क) वसूल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3704/9-आ-1-98-526डी.ए./98, दिनांक 26 दिसम्बर 1998 द्वारा पूर्व में यह निर्देश दिए गये हैं कि फी-होल्ड सम्पत्तियों पर लेबी लगाए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की फी-होल्ड परिसम्पत्तियों पर अनिर्माण शुल्क आरोपित न किया जाय।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय



(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या- (1)/आठ-1-09, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. निजी सचिव, मा० मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन ।
5. निजी सचिव, मा० मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
8. निदेशक(अनुश्रवण), आवास बन्धु, को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के वेब साइट पर अपलोड करते हुए समस्त संबंधितों को सूचित करें।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(एच०पी० सिंह)
अनु सचिव ।